क्र०सं०	जिले का नाम	31 मार्च, 98 तक इकाइयों की सं०
69.	बेहराइच	3663
70.	श्रावस्ती नगर	94
71.	बालमपुर	73
72.	देहरादून	2569
73.	पौड़ीगढ़वाल	2643
74.	तेहरी गढ़वाल	2550
75.	चमोली	2548
76.	रुद्रप्रयाग	48
77.	उत्तर काशी	2045
78.	नैनीताल	3858
79.	अल्मोड़ा	4441
80.	पिथौड़ागढ़	2160
81.	बगेश्वर	—
82.	चम्पावत	—
83.	उधमसिंह नगर	783
84.	नोएडा	3980
85.	ग्रेटर नोएडा	30
	राज्य कुल	342812

स्रोत: आयुक्त तथा उद्योग निदेशक का कार्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग भवन, जी०टी० रोड़, कानपुर-208001.

Compensation by DDA for acquired land

*395. SHRIMATI MALTI SHARMA: SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the public Notice No. F-20(6)96-M.P. dated the 15th January, 1999, wherein DDA had asked for objections and suggestions from residents of Bapraula village in Najafgarh and adjoining areas;

(b) whether Government have acquired the above land measuring 303 acres and has paid the compensation to the original land holders;

(c) if so, the details thereof and when was this compensation paid; and

(d) if not, the basis for DDA issuing such notifications for such land which does not belong to DDA?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) The DDA has reported that a public notice inviting objections/suggestions for change of land-use of an area measuring 125 ha. in village Bapraula proposed for public and semi-public facilities (District Open Jail) has been published by DDA *vide* Notification No. F.-20(6)/96-M.P. dated 15.1.99.

(b) and (c) Acquisition of the land is in progress. Planning clearance for acquisition has been given by DDA. Compensation is paid to the original owners of the land from whom land has been acquired under Land Acquisition Act, 1894.

(d) The process of change of land use is done under section 11(A) of Delhi Development Act, 1957 for which the ownership of land by the DDA is not necessary.

Recruitment in ESIC

*396. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Employees State Insurance Corporation in order to recruit 118 Insurance Inspectors/Managers Grade IV Superintendents have invited applications from open market in recent past;

(b) if so, the criteria to be adopted for such recruitment;

(c) whether some of such recruitments will be made for Delhi offices of E.S.I.Cs;

(d) if so, the details thereof, category-wise; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes, Sir.

(b) In order to fill the vacanices earmarked for direct recruitment for the post of Insurance Inspector/Manager Grade-II/Superintendent, the Employees State Insurance Corporation (ESIC) has decided to conduct an open competitive examination in July, 1999. The candidates who qualify in the competitive examination shall be called for interview. Final selection will be based on aggregate marks obtained in the written examination and interview.

(c) to (e) The posts of Insurance Inspector/Manager Grade-II/Superintendent in the ESI Corporation (ESIC) are interchangeable and are filled by two modes i.e. promotion and direct recruitment. The cadre of these posts and their *inter-se* seniority is centrally maintained by the ESIC on all India basis. Actual placement of the officers from the select list, whether drawn on the basis of promotion or from out of the select list prepared on the basis of direct recruitment, is made at a place where the post is vacant at that particular point of time. While there is no bar in posting of any candidate out of the direct recruitment quota in Delhi, it is not necessary that the candidates selected on the basis of the present examination would be posted in Delhi. In other words, the posts for which the examination is being conducted are not earmarked for any regional office and the candidates to be selected on the basis of this examination will be posted at places where there are vacancies at the time of the availability of select list.

कृषि उत्पादों का निर्यात

*397. **डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किन-किन कृषि उत्पादों के निर्यात की मंजूर दी गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कृषि उत्पादों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) सरकार किन-किन कृषि उत्पादों के निर्यात पर कोई विशेष सहायता या अनुदान देती है; और

(घ) विशेष सहायता या अनुदान प्रदान करने की उपर्युक्त नीति का क्या प्रभाव पड़ा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (घ) गेहूं एवं गेहूं उत्पाद चीनी, मोटे अनाज और दाल (बल्क मात्रा में) को छोड़कर लगभग सभी कृषि उत्पादों का निर्यात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात के कुल मूल्य हैं: 1995-96 में 17496.40 करोड़ रु० 1996-97 में 24362.57 करोड़ रु०, 1997-98 में 23798.37 करोड़ रु० और 1998-99 (अप्रैल-जनवरी) में 20612.24 करोड़ रु०।

कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कुछ कदमों में शामिल हैं:

(i) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरें (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ii) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्म पकवन/क्योंरिंग चेम्बर और गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान; विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (चैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना; उन्नत पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण और प्रसंस्करण एककों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना: विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्रहायता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप उपचार सुविधाओं की संस्थापना; चुनिंदा ताजे फलों और सब्जियों तथा पुष्पोत्पाद मदों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी; क्रेता-विक्रेता बैठकों, और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह-भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना।

(iii) जल्दी नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर